दृष्टिकोण से कम नहीं है। दो दशक से अधिक समय से रूटा (राजस्थान टीचर्स एसोसिएशन) की राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग है लेकिन उसकी बराबर उपेक्षा हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उस पर कोई विचार किया जा रहा है? यदि किया जा रहा है तो कब तक राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है? मेरा दूसरा प्रश्न ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: दूसरा मत पूछिए।

डा॰ अबरार अहमद: यू॰जी॰सी॰ की रिकमेंडेशन्स और प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन्स के संबंध में उड़ीसा से संबंधित प्रश्न के उत्तर में जो कहा है, अगर वही बात राजस्थान पर भी लागू होती है तो माननीय मंत्री जी, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि सरकार जब किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहती है तो सिफारिश उसके अनुरूप आ सकती है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, हमारी सरकार सिफारिशों को मेन्युपुलेट नहीं करती। हम तो जो विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोग कहते हैं उसके अनुसार जाते हैं। समितियां बनी हुई हैं जो विश्वविद्यालयों का एक्रिडिटेशन कर रही हैं कि वे किस स्तर के हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिफारिश करेगा कि उन विश्वविद्यालयों ....(**व्यवधान**)...

डा॰ अबरार अहमद: मानदंड क्या हैं?

श्री सभापति: मानदंड दिए हुए हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: उन विश्वविद्यालयों का स्तरीकरण कहां हो, उनका उन्नयन कहां हो। वे जिनको छांटेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए, उन्हें सहायता दी जाएगी। मानदंडों का इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

DR. M.N. DAS: I am anguished ...(*Interruptions*)... the Education Minister referred to the Central Universities ....(*Interruptions*)

श्री सभापति: देखिए, आप बीच में मत कहिए, मैं आपको हमेशा चांस देता हूं ...(**व्यवधान**)... आज नहीं मिला ...(**व्यवधान**)... दूसरे लोगों को मिल रहा है, मैंने तो नहीं लिया है ...(**व्यवधान**)... बैठिए ...(**व्यवधान**)... बैठिए ...(**व्यवधान**)...

राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र

*447. **श्री जनार्दन पुजारी:** †
श्री के॰ रहमान खान:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

†सभा में यह प्रश्न श्री जनार्दन पुजारी द्वारा पूछा गया।

(क) राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य और मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं;

(ख) अब तक स्थापित किए गए ऐसे केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या नवगठित राज्यों और जिलों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा गया है।

सभा में यह प्रश्न श्री जर्नादन पुजारी द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है।

इसके कार्यकलापों में किसानों की जानकारी और कौशल को अद्यतन बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी विकास के अग्रवर्ती क्षेत्रों में विस्तार कार्मिकों को अभिमुख करने का प्रशिक्षण देना, प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्ट के लिए खेत परीक्षणों की पहचान करना तथा किसानों के खेतों पर उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए अग्रपंक्ति प्रदर्शन करना शामिल है।

कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के दिशा-निर्देशों में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी ''बैकस्टॉपिंग'' मुहैया कराने के लिए मेजबान संस्थान की क्षमता, अपने संसाधनों की हिस्सेदारी हेतु मेजबान संस्थान की उत्सुकता तथा कृषि विज्ञान केन्द्र को इसके सिद्धान्तों, डिजाइन, विधि विज्ञान और उद्देश्यों पर सख्ती से चलाने के लिए मेजबान संस्थान की वचनबद्धता शामिल है।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यों को शुरू करने के लिए 53 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने के अलावा अभी तक 286 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) जी हां। नवगठित राज्यों नामत: छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल में 47 जिलों में से 16 जिलों में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या/पहचाने गये कृषि विज्ञान केन्द्र/क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र शामिल हैं। संबंधित सरकारों से शेष जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों का विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या	सुदृढ़ किए गए क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	17	3
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	–
4.	असम	4	6
5.	बिहार	16	2
6.	छत्तीसगढ़	4	1
7.	दिल्ली	1	–
8.	गोवा	1	–
9.	गुजरात	10	3
10.	हरियाणा	15	–
11.	हिमाचल प्रदेश	9	3
12.	जम्मू और कश्मीर	7	1
13.	झारखण्ड	6	–
14.	कर्नाटक	11	8
15.	केरल	9	2
16.	लक्षद्वीप	1	–
17.	मध्य प्रदेश	20	4
18.	महाराष्ट्र	26	4
19.	मणिपुर	2	–

1	2	3	4
20.	मेघालय	2	–
21.	मिजोरम	2	–
22.	नागालैण्ड	2	–
23.	उड़ीसा	13	2
24.	पाण्डिचेरी	2	–
25.	पंजाब	10	1
26.	राजस्थान	31	1
27.	सिक्किम	1	–
28.	तमिलनाडु	17	3
29.	त्रिपुरा	2	–
30.	उत्तर प्रदेश	32	7
31.	उत्तराचंल	2	1
32.	पश्चिम बंगाल	9	1
	योग	286	53

विवरण-II

नवगठित तीन राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का स्तर

क्र॰ सं॰	राज्य	जिलों की कुल की संख्या	नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या/पहचाने गए कृषि विज्ञान केन्द्रों/क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों की संख्या	शेष जिलों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़	16	6	10
2.	झारखण्ड	18	7	11
3.	उत्तरांचल	13	3	10
	योग	47	16	31

KVKs in States

*447. SHRI JANARDHANA POOJARY:†
SHRI K. RAHMAN KHAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the objectives and guidelines for establishment of Krishi Vigyan Kendras in States;

(b) the number of such Centres established so far, State-wise;

(c) whether proposals have been received for establishment of such Centres in the newly created States and districts; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The objective for establishment of Krishi Vigyan Kendra (KVK) is to provide vocational education in agriculture and allied areas.

The activities include training of farmers to update their knowledge and skills, training of extension personnel to orient them in the frontier areas of technology development, on-farm trials to identify the location specificity of technology, and frontline demonstration to establish the production potential on the farmer's fields.

The guidelines for establishment of KVK include availability of adequate land, capacity of the host institution to provide technology backstopping, willingness of the host institution to share its resources, and commitment of the host institution to run the KVK strictly on its principles, design, methodology and objectives.

(b) So far 286 KVKs have been sanctioned, besides strengthening of 53 Zonal Agricultural Research Stations (ZARS) to take up the additional functions of KVKs. The State-wise details are given in Statement-I. (*See* below)

(c) and (d) Yes, Sir. Out of 47 districts in the newly created States, *viz.*, Chhattisgarh, Jharkhand and Uttaranchal; 16 districts have been

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Janardhana Poojary.

covered with KVKs/ZARSs strengthened/identified for new KVKs. The request has been received from the respective Governments for establishment of KVKs in the remaining districts. The State-wise details are given in Statement-II.

Statement-I

Distribution of KVKs and ZARSS in Different States/Union Territories

Sl. No.	States/Union Territories	No. of KVKs sanctioned	No. of Zonal Agricultural Research Stations (ZARS) strengthened
1	2	3	4
1.	Andaman and Nicobar Islands	1	—
2.	Andhra Pradesh	17	3
3.	Arunachal Pradesh	1	—
4.	Assam	4	6
5.	Bihar	16	2
6.	Chhattisgarh	4	1
7.	Delhi	1	—
8.	Goa	1	—
9.	Gujarat	10	3
10.	Haryana	15	—
11.	Himachal Pradesh	9	3
12.	Jammu and Kashmir	7	1
13.	Jharkhand	6	—
14.	Karnataka	11	8
15.	Kerala	9	2
16.	Lakshadweep	1	—
17.	Madhya Pradesh	20	4
18.	Maharashtra	26	4

1	2	3	4
19.	Manipur	2	—
20.	Meghalaya	2	—
21.	Mizoram	2	—
22.	Nagaland	2	—
23.	Orissa	13	2
24.	Pondicherry	2	—
25.	Punjab	10	1
26.	Rajasthan	31	1
27.	Sikkim	1	—
28.	Tamil Nadu	17	3
29.	Tripura	2	—
30.	Uttar Pradesh	32	7
31.	Uttaranchal	2	1
32.	West Bengal	9	1
	TOTAL	286	53

Statement-II

Status of Establishment of KVKs in Three Newly Created States

Sl.No.	States	Total No. of Districts	No. of KVKs/ ZARSs strengthened/ identified for new KVK	No. of Remaining Districts
1.	Chhattisgarh	16	6	10
2.	Jharkhand	18	7	11
3.	Uttaranchal	13	3	10
	TOTAL	47	16	31

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I would like to know from the

hon. Minister, out of 286 Krishi Vigyan Kendras, how many Kendras are still not functional? If some of them are not functional, what are the reasons for not making them functional? During the Tenth Five Year Plan, what was the allocation; and how many Krishi Vigyan Kendras will be started?

SHRI AJIT SINGH: In the Tenth Five Year Plan, there was a plan to start 66 Krishi Vigyan Kendras, but only 25 of them have been sanctioned by the Ministry so far. And some of them have not started functioning yet, because for starting them we need, at least, 50 acres of land; people have to be hired, and staff also has to be hired. But, at present, there are 286 Krishi Vigyan Kendras, and more than 50 Zonal Research Stations of the Agricultural Ministry are working as Krishi Vigyan Kendras.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Out of 286, how many are not functional?

SHRI AJIT SINGH: Out of 286 Kendras, only 25 Kendras have been sanctioned this year. But I don't have the details of the number of Kendras which have started functioning. I can admit that out of these 25 Kendras also, there are some Kendras, which have not started functioning yet, because they were only sanctioned about six months ago.

SHRI JANARDHANA POOJARY: During the Tenth Five Year Plan, how many proposals were sent by the Karnataka Government, and what was the allocation made by the Government? In your reply, you have given the figures for 2001-02. I would like to know from the hon. Minister, during the Tenth Five Year Plan, how much amount has been allocated, and how many Kendras, from the proposal submitted by the Karnataka Government, will be sanctioned?

SHRI AJIT SINGH: In Karnataka, 95 per cent of the districts are already covered by Krishi Vigyan Kendras, or, zonal stations. So, only five per cent of the districts are left.I don't have the figures of how many proposals have come because many proposals come from every State. As I said, only five per cent of the districts are left. Out of 20 districts, 19 are already covered.

SHRI K. RAHMAN KHAN: The Krishi Vigyan Kendras are very important for imparting training in agricultural education. That is why, agricultural unversities have taken up this programme. Now, you are talking about only the Government run Krishi Vigyan Kendras. And NGOs are allowed to run them. I would like to know from the hon. Minister, out of the total

Kendras, how many are run by NGOs, and how many are run by universities. India being an agricultural country, will the Government consider having a Kendra in every district? The Government should not only motivate the NGOs, but it should see to it that other companies, and organisations also make their contribution towards promoting Kendras. The CII and other organisations also should contribute towards this, so that all the districts in the country are covered.

SHRI AJIT SINGH: Many Krishi Vigyan Kendras are run by NGOs. The Government is not running the Kendras. In fact, out of these 286 Kendras, about 71 are run by the NGO's. And many industries are starting similar kind of Krishi Vigyan Kendras. Not only the CII and the FICCI, but many other industries, which sell agriculture-related products to farmers, like the Mahendra's and many other companies, are setting up these Kendras. We are also planning that these Kendras should not only educate farmers, but they should work as service centres, so that all kinds of testings, soil testing, pesticides testing, etc. may be provided at KVKs. We are seeing that the Krishi Vigyan Kendras become a vehicle not only for education, but also a centre for imparting training. We are seeing that they also become a centre for providing other services and marketing help, needed by farmers.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, in India, there are 286 Krishi Vigyan Kendras, but there is no coordination between KVKs and farmers. The technologies developed in the KVK laboratories never reach farmers. Therefore, I request the hon. Minister to ensure that new technologies reach farmers. As the Government is aware, in many States, there is an acute scarcity of water. I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal with the Government to encourage farmers to go in for dryland farming and raise such crops for which little water is used. Part (b) of my question is, how much amount has been spent for maintaining the KVKs? Has any analysis been done with regard to the performance of the KVKs?

SHRI AJIT SINGH : Sir, the mandate of the KVKs is to take the technology from lab to farmers. If the hon. Member has any complaint about some particular KVK, we will look into that. An optimum utilisation of water is one of the things that we need today. Many KVKs, in the dryland farming areas, are working on this principle.

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सूची में जो आपने राज्यवार सारे केन्द्र दिए हैं, इनमें से कितने केन्द्र, दोनों तरह के स्वीकृत कृषि विज्ञान और कृषि अनुसंधान केन्द्र, इस बजट ईयर में फंक्शन करना शुरू कर देंगे और कितने अगले बजट ईयर में फंक्शन करना शुरू कर देंगे?

SHRI AJIT SINGH: Sir, 25 KVKs have been sanctioned during the last 6-8 months. In the Tenth Plan, there is a provision for 66 KVKs, out of which 25 have already been sanctioned. It will take time, depending upon things, like acquiring land and other things, etc.

Rakes for animal fodder

*448. SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Andhra Pradesh has requested the South Central Railway to provide more rakes for transportation of animal fodder to drought affected areas in the State, free of cost; and

(b) if so, Government's response to the request?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Andhra Pradesh Government had requested the Railways for transportation of Animal Fodder free of cost to drought affected areas in the State. Government of Andhra Pradesh was advised on 21.10.2002 that transportation of fodder free to the notified drought affected areas had already been permitted by Ministry of Railways for a period of two months from 31.8.2002 to 31.10.2002. This concession has further been extended up to 31.12.2002. So far no demand has been placed with the Railways.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, since Andhra Pradesh is faced with severe drought, there is a scarcity of fodder. This question was put at that time also. While making the statement, the hon. Prime Minister, on 18th, had assured this House that till June, 2003, fodder will be allowed to be transported through railways, free of cost, But, today's